मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

ओयो होटल का सेक्स धंधा 3
पानी माँग गए थे मोदी 4
जानकर हैरान हो जाएँगे 5
देवता को संघ का सहारा 6
स्मार्ट सिटी का ड्रामा 8

वर्ष 34 अंक -8 फ़रीदाबाद 6-12 जनवरी 2019 फोन - 9999595632 ₹2.50

दिहाड़ीदार डीजीपी संधू का पुलिस में नियमित भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा

फ़रीदाबाद (मजदूर मोर्चा)

बीते रविवार यानी 30 दिसम्बर को नहर पार स्थित पुलिस कॉलोनी के मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा उद्घाटन अवसर पर दिहाड़ीदार डीजीपी बलजीत सिंह संधू भी यहां आये थे। वैसे उद्घाटन एवं नारियल फ़ोड़ने जैसे ड्रामे करने में तो खट्टर सहित सभी नेता माहिर हैं; वे बिना डीजीपी के भी यह काम कर सकते थे। परन्तु खट्टर के कृपा-पात्र संधू चापलूसी का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते थे, लिहाज़ा वे चंडीगढ़ से चल कर खुद तो आये ही साथ में वहां से अनेकों अफ़सरों को भी लाये। इतना ही नहीं शोभा बढाने के लिये आस-पास के ज़िलों से भी अफ़सरों को आमन्त्रित किया जिन में से कुछ तो आये भी।

इस अवसर पर डीजीपी संधू ने सेक्टर 31 स्थित एक होटल में लंच का आयोजन किया। इसमें यहां रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों को भी विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के उच्च पुलिस अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को तो उन्होंने पूर्णतया समाप्त कर दिया है और अब वे निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जुटे हैं।

सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहती है। यदि पुलिस के, विभिन्न स्तर पर तैनात, मुखिया खुद भ्रष्ट नहीं हैं, वे मलाईदार पदों की तैनातियां नीलाम नहीं करते हैं

अथवा अपने मातहतों से वसूलियां नहीं उगाहते हैं तो निचले स्तर के अधिकारी रिश्वतखोरी करेंगे भी तो डर कर व छिप कर करेंगे। परन्तु जब उच्चाधिकारियों की मांगों की पूर्ति करनी पड़ती है तो फ़िर वे खुला खाते हैं और नंगे नहाते हैं, यानी उन्हें अपने उच्चाधिकारियों का कोई भय नहीं रहता, वे बेखौफ़ होकर जनता को लूटते हैं। हरियाणा में यही हो रहा है। छोटे अधिकारी तो अक्सर कमाते ही अपने उच्चाधिकारियों के लिये हैं।

पुलिस विभाग के अपने कायदे-कानून (पुलिस रूल) इतने कड़े हैं कि छोटा अधिकारी अपने से ऊपर वाले अधिकारी की मर्जी के बिना सांस तक नहीं ले सकता और उच्चाधिकारी उसकी हर सांस को गिन सकता है। पुलिस रूल के मुताबिक एक एएसआई अपने मातहत हवलदार को निलंबित कर सकता है, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर सकता है। इतनी शक्तियां उच्चाधिकारियों के पास होने के बावजूद भी यदि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कायम है तो लानत है ऐसे उच्चाधिकारियों पर।

समझना कठिन नहीं है कि पुलिस का जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है उसके लिये वास्तव में उच्चाधिकारी ही उत्तरदायी हैं। वे अपनी (मलाईदार) तैनातियों के लिये जिस तरह से राजनेताओं के तलवे चाटते हैं और बदले में फ़िर उनके इशारों पर नाचते हैं उसी से सारे महकमे का सत्यानाश हुआ है।

चिकित्सा के लिये नहीं, लुटाने के लिये बजट है

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अस्पताल व चिकित्सा केन्द्र खोलने और जो खुले हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में स्टाफ़, दवायें व अन्य साजो सामान खरीदने के लिये सदैव बजट का अभाव रहता है। परन्तु अनावश्यक कामों पर लुटाने के लिये बजट की कोई कमी नहीं।

कमीशनखोरी के चक्कर में गांव कुराली स्थित सीएचसी (सामुदायिक हैल्थ सेंटर) में, गार्ड, स्वीपर, चपरासी आदि के पदों पर 17 लोग़ों को ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किया गया है। नियमानुसार इस तरह के स्टाफ़ की नियुक्ति केवल वहां हो सकती है जहां मरीज़ दाखिल रहते हों जबकि कुराली सीएचसी में मरीज़ दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। और तो और इस सीएचसी में दिन भर में मात्र 20-25 से अधिक मरीज ओपीडी में नहीं आते, आकर करें भी क्या, क्योंकि वहां है ही कुछ नहीं। इसके बावजूद वहां 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती को मंजूरी दे दी गयी। इसी तरह की मंजूरी खेड़ी कलां की सीएचसी में भी देने का प्रयास किया गया था लेकिन वहां तैनात इन्चार्ज डॉक्टर ने इसे सख्ती से रोक दिया।

जानकारों के मुताबिक यह घोटाला अस्पताल में तैनात सांगवान नामक एक फ़ार्मेसिस्ट ने स्टाफ़ सप्लाई करने वाली फ़र्म मार्शल सिक्युरिटी सर्विसेज के मालिक महेन्द्र दीक्षित से मिल कर कार्यवाहक सीएमओ डॉ. बीर सिंह सहरावत से करवाई थी। सहरावत को 31 दिसम्बर को रिटायर होना था, सो हो गये लेकिन रिटायर होने से पहले सांगवान जितने घोटाले करा सकता था करा लिये। मजे की बात तो यह है कि कार्यवाहक सीएमओ सहरावत के पास वित्तीय शक्तियां भी नहीं थीं, फ़िर भी उन्होंने इस तरह की मंजूरी दे दी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सीएमओ सहरावत ने रिटायरमेंट से दस दिन पूर्व अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अनेकों फाइलें निकाली। उन सब की जांच होने पर और भी घोटाले सामने आयेंगे।

उक्त सिक्युरिटी सर्विसेज चलाने वाला

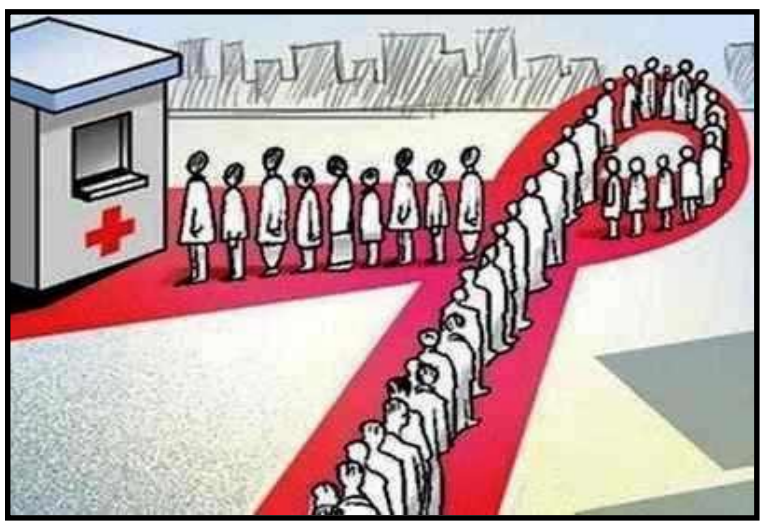

महेन्द्र यह धंधा पलवल के सिविल अस्पताल में भी करता रहा है जहां सहरावत ने अपनी वहां की तैनाती के दौरान उसे ठेका दिया था। उसी आधार पर ठेकेदार ने यहां बीके अस्पताल का ठेका भी तत्कालीन सीएमओ गुलशन अरोड़ा से प्राप्त कर लिया था। यह सब ठेकेदारियां तब चल रही हैं जबकि वह अपने कर्मचारियों का पीएफ़ व ईएसआई का पैसा उनके वेतन से काट कर जमा कराने की बजाय गबन कर चुका है और ब्लैक लिस्ट भी हो चुका है। जानकार बताते हैं कि इस चोर ठेकेदार को स्थानीय सांसद कृष्णपाल गूजर के एक तथाकथित पीए मलिक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के एक चमचे भारद्वाज का भी संरक्षण प्राप्त है। जानकार बताते हैं कि यह ब्लैक लिस्टेड अपने उक्त संरक्षकों की नियमित हर प्रकार की सेवा करता है।

पूर्व सीएमओ रिटायर होने के बावजूद भी नियमित रूप से बीके अस्पताल में धक्के खाने आ रहा है जहां उसकी कुत्ते जितनी भी पूछ नहीं। और तो और उनका चापलूस दल्ला सांगवान भी अब कहीं नज़र नहीं आता। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि उस सांगवान ने सीएमओ की विदाई पार्टी के नाम पर डॉक्टरों के अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक से भी उगाही करके 30000 से अधिक रकम एकत्र करके गायब हो गया। जाहिर है ऐसे में लोग़ों को न खाना मिला न विदा होने वाले को कोई उपहार।

मुख्यमंत्री खट्टर का ढपोल-शंखनाद : बीते रविवार खोला 700 करोड़ी का पिटारा

फ़रीदाबाद (म.मो.) पूरे 4 साल तक राज्य भर की जनता को लारे-लप्पे देने व जुमलेबाज़ी से बहलाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहर की जनता को चुनाव से 100 दिन पहले बेवकूफ़ बनाने के लिये सेक्टर 12 स्थित मैदान में शंखनाद रैली का आयोजन किया। विदित है कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व खट्टर जी देश भर में शंख बजा-बजा कर आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) का प्रचार किया करते थे। इस नाते इन्हें शंख बजाने का अच्छा-खासा अनुभव एवं महारत हासिल है। इसी से प्रसन्न होकर संघ ने इन्हें हरियाणा प्रांत बतौर इनाम सौंप दिया।

संघ के प्रचार हेतु तो शंखनाद ठीक था परन्तु सत्ता एवं वोट की राजनीति के लिये केवल शंखनाद से काम चलने वाला नहीं। इसी सच्चाई के मद्देनज़र संघ के दिशा निर्देशन में उन्होंने यहां ढपोल-शंख नाद करते हुए 700 करोड़ रुपये के 'विकास कार्यों' की घोषणायें कर डाली। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की घोषणा वे अकेले यहां कर गये हों, यह काम वे राज्य भर के हर ज़िले, तहसील व गांवों तक में करते आ रहे हैं। झूठ के ये जुमले फ़ेंकने का काम अकेले खट्टर जी नहीं बल्कि निचले

स्तर पर प्रत्येक विधायक व मंत्री तथा ऊपरी स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी व तमाम केन्द्रीय मंत्री सांसद करने में जुटे हुए हैं। यदि इन सब घोषणाओं को जोड़ा जाये तो कुल रकम हरियाणा के कुल बजट से भी कई गुणा अधिक बनती है। जाहिर है जब इतनी धन राशि सरकारी खजाने में है ही नहीं तो घोषित कार्यों पर खर्च कहां से और कैसे होगा? परन्तु यह खर्च करने की चिन्ता किसको है, चिन्ता तो तब हो न जब कोई काम करना हो। बीते चार वर्षों में खट्टर द्वारा घोषित कोई काम हुआ हो ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। खट्टर ही क्या मोदी द्वारा घोषित भी कोई काम हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। मंझावली का यमुना पुल व स्मार्ट सिटी का ड्रामा इसके बेहतरीन जीते जागते उदाहरण हैं।

राजकोष से पैसा खर्च करके जनता के लिये कोई काम करना तो दूर की बात, जो काम बिना पैसे या नाम मात्र के खर्च से ही सम्भव हो सकते हैं वे काम भी इस सरकार की समझ से बाहर हैं, समझ कहां से आये समझ पर तो पत्थर पड़े हैं या गाय का गोबर। 'मज़दूर मोर्चा' ने कई बार समझाने का प्रयास किया है कि हरियाणा के कुल 45 लाख परिवारों में से 30 लाख परिवार ईएसआईसी कवर्ड हैं, जिनके इलाज एवं चिकित्सा आदि के लिये भरपूर पैसा ईएसआई निगम के खजाने में है और ईएसआई निगम इसे देनें से मना भी नहीं करता पर इस ढपोल-शंखों की समझ में यह बात कभी नहीं आई और आने की सम्भावना भी नहीं दिखती।

बीते इन चार वर्षों में पब्लिक इन जुमलेबाजों की पूरी जुमलेबाज़ी को समझ चुकी है; इसलिये इनकी पार्टी बखूबी समझती है कि इनके जुमले सुनने को कोई आने वाला नहीं और यदि कोई सुनने वाली भीड़ न पहुंचे तो पार्टी एवं सरकार की बड़ी भारी बेइज्जती होती है; लिहाजा भाड़े पर भीड़ जुटाने का इन्तजाम भी किया गया। यह काम स्थानीय विधायक एवं उद्योग मंत्री विपुल गोयल के जिम्मे रहा। उन्होंने प्रचार हेतु शहर भर को पार्टी के झंडों, बैनरों व पोस्टरों से आंटने के साथ-साथ दिहाड़ी पर मज़दूरों व फैक्ट्रियों की लेबर से पंडाल को भरने का असफ़ल प्रयास भी किया। इतना ही नहीं ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर सेक्टर 28 स्थित ट्रैफ़िक पुलिस लाइन में खड़े करीब एक हजार ऑटो रिक्शा भी छुड़वा कर भाड़े की भीड़ ढोने पर लगा दिये, स्कूल बसें इनके अतिरिक्त थीं। इसके बावजूद पंडाल भरा नहीं जा सका।

इस रैली से भाजपाइयों को एक और बड़ी उम्मीद यह थी कि स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर तथा विपुल गोयल के बीच की राड़ खत्म करा कर पार्टी को और मजबूत किया जायेगा, परन्तु गूजर न तो स्वयं रैली में आये और न ही अपने समर्थकों को आने दिया यहां तक कि शहर की मेयर सुमनलता तक रैली में नहीं पहुंची। जाहिर है इससे पार्टी में बढ़ती फूट जनता के सामने खुल कर आने लगी है जिसका प्रभाव भी आगामी चुनावों में देखने को मिलना स्वाभाविक ही है।